संख्या-62/2018/257/35-3-2018-1(42)/2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-श्रावस्ती में शासनादेश सं0 16/2018/44/35-3-2018-1(42)/2017, दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु रू.169.33 लाख (रू.एक करोड़ उन्हत्तर लाख तैतीस हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू0 101.59 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय,**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में** रू. 67.74 लाख (सरसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	**प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन**	**केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि**	**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	2	3	4	5	6
		कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग			
हरिहरपुररानी	1	तुरूसमा सम्पर्क मार्ग का निर्माण. 0.43 किमी.	36.24	21.74	14.50
सिरसिया	2	पूरेवाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण।ल.0.75 किमी.	44.89	26.93	17.96
सिरसिया	3	परसोहना मिनी स्टेडियम सम्पर्क मार्ग निर्माण ल. 0.18 किमी.	15.16	9.10	6.06
		योग	96.29	**57.77**	**38.52**
		कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग			
हरिहरपुररानी	1	ककरदरी से मरीमाता मंदिर मार्ग पर 2 गुणे 5 मी.आर.सी.सी.पुलिया का निर्माण	73.04	43.82	29.22
		कुल योग	169.33	101.59	67.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सडक निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- **कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीक़त लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।**

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-03-सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5-382/दस-2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-62/2018/257(1)/35-3-2018-1(42)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव,लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त,देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी,श्रावस्ती ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/लोक निर्माण अनुभाग-9 /ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी,श्रावस्ती ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in